किसानों के लिए 4000 करोड़ की एग्रीज नीति

कैबिनेट फैसला 1

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक सहायतित 4000 करोड़ रुपये की यूपीएग्रीज (उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेथनिंग) परियोजना को मंगलवार को मंजूरी दे दी है।

यह परियोजना प्रदेश के आठ मंडलों के 28 जिलों में लागू की जाएगी। इसमें सात जिले बुन्देलखण्ड के हैं, जबकि घाघरा और सरयू के उत्तर में स्थित गोरखपुर, बस्ती एवं देवीपाटन मंडल के जिलों के अलावा सरयू नदी के दक्षिण में पड़ने वाले आजमगढ़, वाराणसी एवं मिर्जापुर मंडल के जिले शामिल हैं। इसके तहत किसानों को सबसे बेहतरीन बीज, उच्च तकनीक एवं मशीनें आदि देकर उनसे 6.15 लाख हेक्टेयर भूमि में मुख्य फसलों के अलावा कुछ नकदी फसलों की आधुनिक खेती कराई जाएगी। परियोजना 2029-30 तक चलेगी।

- सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परियोजना को मंजूरी

परियोजना में 70% राशि ऋण के रूप में देगा विश्वबैंक

- कुल 4000 करोड़ की यूपीएग्रीज परियोजना में 70% राशि ऋण के रूप में विश्वबैंक देगा। शेष 30% राशि राज्य सरकार खर्च करेगी।
- 3737 करोड़ रुपये विश्वबैंक देगा जबकि 166 करोड़ राज्य सरकार अपने स्रोतों से खर्च करेगी।
- विश्वबैंक ने राज्य सरकार को यह ऋण 35 वर्षों के लिए मंजूर किया है जो 1.23% के ब्याज पर है।
- ऋण का राज्य सरकार को डॉलर के बजाय येन में भुगतान करना है जो डॉलर की तुलना में सस्ता पड़ेगा।
- परियोजना क्षेत्र के किसानों को मौसम पूर्वानुमान से लेकर रोग-व्याधि आदि की आशंकाओं की जानकारी पहले से दी जाएगी।
- किसानों का डिजिटल प्लेटफार्म बनाया जाएगा, ताकि एक क्लिक पर सारी सूचनाएं उपलब्ध हो सके।

12 बस स्टेशन विकसित किए जाएंगे

2 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 12 और बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। अब इन्हें विकसित करने के लिए विकासकर्ताओं को लैटर ऑफ इंटैंट देने की मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। परिवहन निगम ने 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का लक्ष्य रखा था। अभी तक ये 12 बस स्टेशन बचे हुए थे।

मोटे अनाज की खरीद नीति को मंजूरी

3 कैबिनेट ने मोटा अनाज खरीद नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा का 2625 रुपये, ज्वार (हाईब्रिड) 3371 रुपये, और ज्वार (मालदाण्डी) 3421 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की गई है। सरीफ सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का, ज्वार एवं बाजरा की खरीद एक अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक होगी।

कैबिनेट ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 200 करोड़ की मंजूरी दी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर एग्रो क्लस्टर बनाया जाएगा। आठ क्लस्टर बन चुके हैं, कुछ पर काम शुरू है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बनेंगे।

यहां लागू होगा प्रोजेक्ट: मिर्जापुर, सोनभद्र भदोही, वाराणसी, गाजीपुर, चन्दौली, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच श्रावस्ती, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर एवं जालौन जिले के नाम शामिल हैं।